

अपील राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 संख्या 06 / 2020 (GCMS 2020/00154) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट अग्रवाल क्रमांक 52एफ-509326) बनाम संजय अग्रवाल, तहसीलदार, श्रीगंगानगर वगैरे
18.01.2023



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने श्री संजय अग्रवाल, तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2001 के तहत अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा संवेदनशील लम्बित अपराधिक रिविजन में जानबूझकर दूसरे पक्षकार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्यों से पुनः जांच न कर श्रीमान् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्री उम्मेद सिंह जी के आदेशों की सरासर जानबूझकर उल्लंघना की है, इसलिए उक्त अधिकारियों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपनी अपील दिनांक 14.08.2020 के द्वारा निम्न अनुतोष चाहा है:

1. उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना में 188 आईपीसी के तहत कार्यवाही की जावे एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री संजय जी अग्रवाल तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के विरुद्ध की जावे।
2. आदेशों की अवहेलना करने पर 5000/- रुपये जुर्माना धारा 7 के अन्तर्गत अधिरोपित किया जावे।
3. जांच किसी अधिकारी से करवायी जावे।




BN
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी का प्रकरण राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत बने नियमों के तहत जारी अनुसूची में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में नहीं आता है और न ही उक्त आदेश राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जारी किया गया है।

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाओं पर लागू होते हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम के अनुसार विभिन्न विभागों के पदाभिहित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में उक्त सेवाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध करवानी होती है और समय सीमा में सूचना उपलब्ध न करवाने पर अधिनियम की धारा 6 के तहत अपील करने का अधिकार है और वांछित सेवा के लिए राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 नियम 3 के तहत आवेदनकर्ता को पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने पर उसकी अभिस्वीकृति जारी की जाती है। अपीलार्थी द्वारा उक्त गारंटी अधिनियम के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत करने की रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है।

चूंकि उक्त प्रकरण राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत बने नियमों के तहत जारी अनुसूची में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में नहीं आता है और न ही उक्त आदेश राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जारी किया गया है। इसलिए उक्त अपील राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत ग्रहण करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर